आज़ादी का अमृत महोत्सव

साप्ताहिक सूचना पत्र

(दिनांक 12.06.2023 से 18.06.2023)

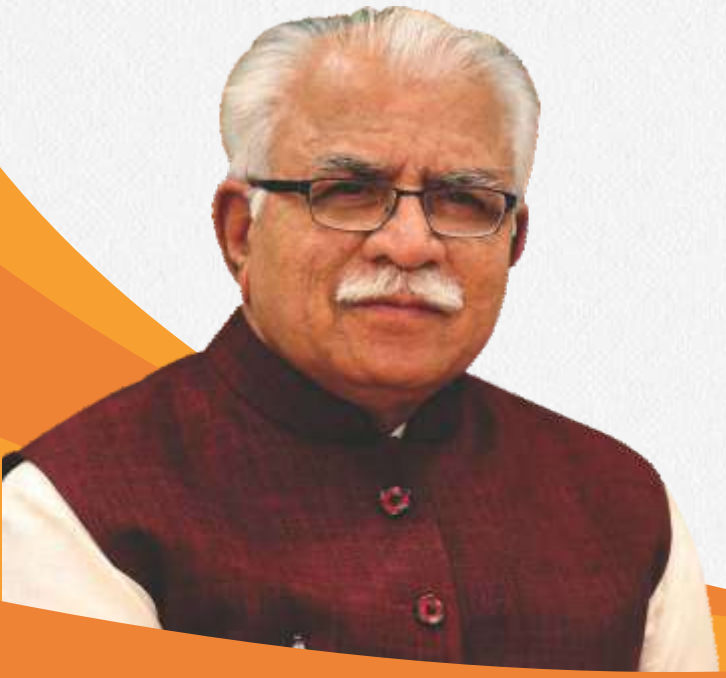

भारतीय जनता पार्टी
हरियाणा

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल नगर निगम में जनसंवाद कार्यक्रम

(दिनांक 12.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने सोमवार को करनाल नगर निगम के वार्ड–16 में जनसंवाद कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित कर कहा कि प्रदेश के लोगों का जीवन सरल हो, इसके लिए हरियाणा सरकार ने अनेक कल्याणकारी नीतियां बनाई हैं। उन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार को रोकने के लिए हमारी सरकार कृतसंकल्प है। हमारी सरकार में लोगों को योजनाओं का सीधा लाभ पहुंच रहा है। अब सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जाती है जबकि पहले लाभार्थी तक पहुंचते पहुंचते राशि रास्ते में ही गायब हो जाती थी। जनसंवाद में एक मामले पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि करनाल की कोढ़ी कॉलोनी में प्राइमरी स्कूल खोलने की मांग को मंजूर कर

लिया गया है। इस पर जल्द काम शुरू हो जाएगा।

एक शिकायतकर्ता की राशन कार्ड कटने संबंधी शिकायत पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा उक्त व्यक्ति का कार्ड इसलिए कटा क्योंकि उन्होंने लोन लेने के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरी थी। पिछले दो साल में किसी ने रिटर्न नहीं भरी है तो राशन कार्ड के लिए रिटर्न में दिखाई गई इनकम को नहीं माना जाएगा। जिन लोगों ने इनकम टैक्स रिटर्न भरी है, उसका असर उनके राशन कार्ड पर पड़ा है। एक शिकायतकर्ता की पेंशन शुरू नहीं होने की बात पर उन्होंने कहा कि आयु का कोई भी प्रमाण दें, आपकी पेंशन शुरू करा दी जाएगी।

प्रॉपर्टी आईडी से संबंधित उन्होंने कहा की किसी भी प्रकार की समस्या नहीं रहने दी जाएगी। इसके लिए विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं। हर किसी की समस्या का समाधान किया जायेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जनसंवाद के दौरान उन्होंने कहा कि एक लाख 80 हजार रुपए वार्षिक आय वाले परिवारों को चिरायु योजना के तहत हरियाणा सरकार ने पांच लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। जिन परिवारों की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपए से तीन लाख रुपये तक है, उन परिवारों से कुछ प्रीमियम राशि लेकर उन्हें भी पांच लाख रुपए तक का लाभ देने के लिए योजना में शामिल करने पर विचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि परिवार पहचान पत्र योजना के लागू होने के बाद घर बैठे प्रदेश में साढ़े 12 लाख नए बीपीएल राशन कार्ड बने हैं। एक युवक द्वारा नौकरियों में पारदर्शिता से चयन होने की बात कहने पर जनसंवाद में उपस्थित लोगों ने तालियां बजाकर समर्थन दिया। इस पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि अब पढ़ने वाले युवकों को पारदर्शिता के साथ सरकारी नौकरियों में मौका मिलता है। पहले सरकारी नौकरियों के लिए सिफारिश चलती थी, अब योग्य का चयन होता है। उन्होंने कहा कि जितनी भी शिकायतें इस जनसंवाद में मिली हैं, इन सभी पर कार्रवाई होगी। सभी शिकायतें संबंधित विभागों को ऑनलाइन भेजी जाएंगी जिनका समाधान निर्धारित समय अवधि में संबंधित अधिकारी को करना होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

करनाल ब्राह्मण सभा के प्रतिनिधियों से मुलाकात

(दिनांक 12.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी अपने करनाल प्रवास के दौरान सोमवार सुबह पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में ब्राह्मण सभाओं के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने अपना वायदा निभाते हुए जिला करनाल की ब्राह्मण सभा को 21 लाख रुपये, जिला मोहियाल ब्राह्मण सभा को 5 लाख रुपये और मॉडल टाउन ब्राह्मण सभा को 5 लाख रुपये का चेक सौंपा। इस चेक को जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से प्रधान सुरेंद्र शर्मा बडौता, जिला मोहियाल ब्राह्मण सभा की तरफ से पूर्व प्रधान विनोद मेहता व मॉडल टाउन ब्राह्मण सभा की तरफ से एडवोकेट राहुल बाली ने लिया। उन्होंने कहा कि परशुराम महाकुंभ में किया अपना वायदा निभाया है। भविष्य में भी ब्राह्मण समाज द्वारा की गई मांगों पर विचार करके उन्हें पूरा किया जाएगा। कि भगवान परशुराम पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है तथा परशुराम जयंती पर हरियाणा सरकार द्वारा राजपत्रित अवकाश घोषित और कैथल में मेडिकल कॉलेज का नाम भगवान परशुराम के नाम पर रखा गया है। उन्होंने पहरावर गांव की जमीन के कागजात गौड़ ब्राह्मण सभा को सौंपने का ऐलान किया था, जो पूरा कर दिया है। इसके अतिरिक्त करनाल में कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने वाले रोड का नाम भगवान परशुराम मार्ग किया और करनाल अस्पताल चौक का नाम भगवान परशुराम चौक किया और इसके सौंदर्यीकरण का बजट भी पास कर दिया। करनाल के फव्वारा चौक का नाम भी भाई मति दास व भाई सति दास चौक करने व उनकी प्रतिमा स्थापित करने के लिए बजट पास कर दिया गया है। हरियाणा सरकार में निरंतर विकास कार्य किए जा रहे हैं। भविष्य में ऐसे ही प्रदेश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ेगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ

(दिनांक 12.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की 10 फेसलेस सेवाओं का शुभारंभ करते हुए कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की इन सेवाओं से डिजिटल सशक्तिकरण व नागरिकों की सुविधाओं की दिशा में एक ओर महत्वपूर्ण कदम है।

जो हरियाणा के नागरिकों को सुलभ और उपयोगकर्ता के अनुकूल सेवाएं प्रदान करने की दिशा में एक मील का पत्थर साहिब होगा। इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने फेसलेस सेवाओं का ब्रोशर भी लांच किया।

उन्होंने कहा कि हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण का उद्देश्य प्रौद्योगिकी के माध्यम से पारदर्शी व नागरिक केंद्रित सेवाएं प्रदान करना और राज्य के समग्र

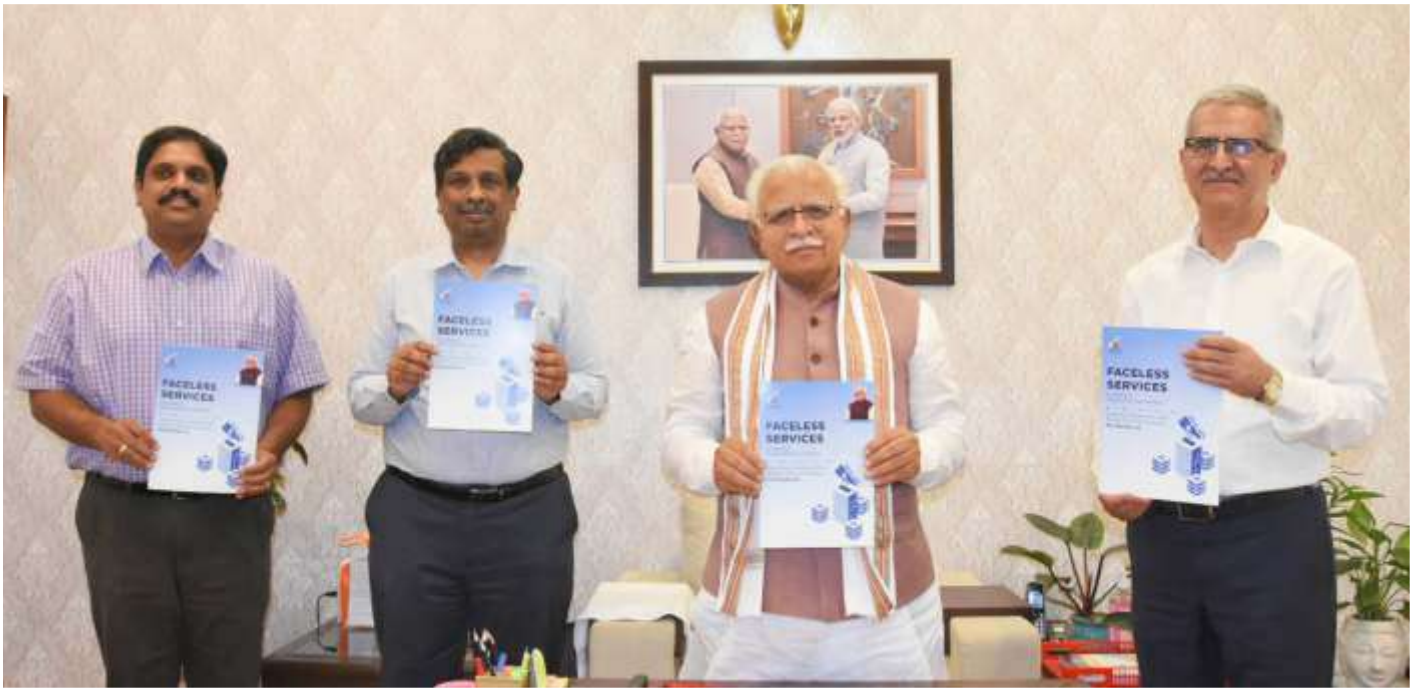

विकास और कल्याण में योगदान देना है। हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण सेवाओं का लाभ आवंटी अब व्यक्तिगत रूप से एस्टेट कार्यालय जाने की आवश्यकता के बिना कहीं से भी उठा सकते हैं। ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म 24'7 सुलभ है, जिससे नागरिक आसानी से अपने आवेदन जमा कर सकते हैं और अपनी सुविधानुसार सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि फेसलेस सर्विस से पारदर्शिता बढ़ेगी क्योंकि आवेदक अपने आवेदनों की स्थिति को ट्रैक कर सकते हैं और ऑनलाइन अपडेट प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा, सिस्टम की फेसलेस सर्विस आवंटन प्रक्रिया में निष्पक्षता और निष्पक्षता को बढ़ावा देती है, जिससे सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित होते हैं।

उन्होंने कहा कि फेसलेस सर्विस के शुभारंभ से हरियाणा के नागरिकों को कई लाभ होंगे और आवंटी अब विभिन्न सेवाओं के लिए आवेदन कर सकते हैं। जैसे स्थानांतरण अनुमति पत्र, नॉन डयूज प्रमाण पत्र, गैर–भार प्रमाण पत्र, इंडिपेंडेंट तल–स्थानांतरण अनुमति पत्र, मोर्टगेज अनुमति पत्र, इंडिपेंडेंट तल पुर्नआवंटन पत्र, डी–मोर्टगेज अनुमति पत्र, स्थानांतरण अनुमति रद्द करना, आवंटन पत्र (ई–नीलामी) और पुनः आवंटन पत्र की सुविधाएं प्रदान की जाएगी।

इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण की वैन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह वैन एचएसवीपी के हर सेक्टर में जाकर लोगों को एचएसवीपी द्वारा दी जा रही योजनाओं की जानकारी देगी और उन्हें जागरूक करने का काम करेंगी। माननीय मुख्यमंत्री जी को बैठक में बताया गया कि पिछले वर्ष इन सेवाओं का 62 हजार लोगों ने मैनुअल माध्यम से लाभ लिया है। लेकिन अब इन सभी सेवाओं का लाभ ऑनलाइन माध्यम से ही मिलेगा। उपयोगकर्ता को इन सेवाओं का लाभ उठाने के लिए आवंटी कॉर्नर में लॉगिन करना होगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

भारतीय विदेश सेवा अधिकारियों से मुलाकात

(दिनांक 12.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने आज भारतीय विदेश सेवा के अधिकारियों से मुलाकात कर कहा कि राज्य में विदेश सेवा विभाग का गठन किया गया है जो प्रदेश के युवाओं को रोजगार के अवसर मुहैया करवाने में सहयोग कर रहा है। इसके अलावा प्रदेश के नागरिकों का जीवन स्तर को ऊंचा उठाने एवं आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए नई–नई पहल जा रही हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में उद्योग, व्यापार, पर्यटन को बढावा देने के लिए कारगर कदम उठाए जा रहे हैं ताकि प्रदेश के युवाओं को ज्यादा से ज्यादा रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें। हरियाणा में परिवार पहचान पत्र, स्वामित्व जैसी महत्वाकांक्षी योजनाएं शुरू की। इन योजनाओं का भारत के अन्य राज्यों में भी अनुसरण किया जा रहा है। इसके अलावा बीपीएल सूची में नए परिवारों के नाम शामिल करने के लिए आय का पैमाना बढाकर 1.80 लाख रुपए किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि पंचायतों में विकास कार्य करवाने के लिए ई टेंडरिंग प्रक्रिया शुरू की गई है। इस तरह की योजनाओं से भ्रष्टाचार पर अंकुश लग रहा है। प्रदेश के तालाबों का सौंदर्यीकरण करने के लिए हरियाणा तालाब एवं अपशिष्ठ जल प्रबंधन प्राधिकरण का गठन किया गया है। इसके माध्यम से प्रदेश के सभी तालाबों की कायाकल्प करने का कार्य किया जा रहा है। इसके साथ ही तालाबों पर पगडण्डी बनाई जा रही हैं ताकि लोगों के लिए एक रमणीक स्थल के रूप से बेहतर स्थान उपलब्ध हो सके। उन्होंने कहा कि जल संरक्षण के लिए मेरा पानी मेरी विरासत योजना क्रियान्वित की गई है। किसानों को फसल विविधीकरण अपनाने और धान की पैदावार कम करने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

कैथल में व्यापारी सम्मेलन

(दिनांक 13.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कैथल में आयोजित व्यापारी सम्मेलन को संबोधित कर यह घोषणा करते हुए कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडियों में चारदीवारी, शेड के निर्माण व मरम्मत, गेट तथा सफाई व्यवस्था इत्यादि कार्यों के लिए एक नई नीति बनाई जाएगी।

इसके अंतर्गत एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसमें आढ़ती भागीदार होंगे। इस समिति को मार्केट फीस में से कुछ राशि उपलब्ध करवाई जाएगी, जिससे समिति मंडी के कार्य अपने स्तर पर करवा सकेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेशभर में सब्जी मंडी में लगने वाली मार्केट फीस व एचआरडीएफ दर को अब एकमुश्त तय किया जाएगा।

इससे संबंधित नियमों में संशोधन के विधेयक को विधानसभा से पारित किया जा चुका है। अभी 2 प्रतिशत मार्केट फीस व 2 प्रतिशत एचआरडीएफ की दर लागू है। आढ़तियों की मांग पर सरकार

ने विचार करते हुए इसे एकमुश्त करने का निर्णय लिया है। उन्होंने कहा कि कैथल में ट्रांसपोर्ट नगर में हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा नीति के तहत व्यापारियों को दुकानें बेची गई थी।

लेकिन नीति में कुछ नियम व शर्तों के कारण आज व्यापारी अपनी दुकानें आगे बेच नहीं पा रहे हैं। सरकार ने व्यापारियों की कठिनाई को समझते हुए यह निर्णय लिया है कि ऐसे व्यापारियों के लिए नई नीति बनाई जाएगी और उन्हें नियमों में छूट दी जाएगी, जिससे वे अपनी दुकानें बेचने में सक्षम हो सकेंगे। प्रदेशभर में शहरों में बने सरकारी गोदामों को शहर से बाहर शिफ्ट करने के लिए भी नीति बनाई जा रही है। जल्द ही ऐसे गोदामों को शहर से बाहर स्थापित किया जाएगा।

मंडियों में दुकानों से संबंधित चल रहे विवादों के निपटान के लिए सरकार द्वारा चलाई गई विवादों का समाधान योजना को 1 वर्ष की अवधि के लिए बढ़ाने की घोषणा की। नैफेड द्वारा की जाने वाली फसलों की खरीद पर 1.25 प्रतिशत हैंडलिंग चार्जिस आढ़तियों को देने की घोषणा हरियाणा सरकार द्वारा पहले ही की जा चुकी है। व्यापारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने व्यापारियों के कल्याण के लिए अनेक योजनाएं चलाई हैं।

हरियाणा में व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए राज्य सरकार ने व्यापारी कल्याण बोर्ड का भी गठन किया है। इसके अलावा, मुख्यमंत्री व्यापारी सामुहिक निजी दुर्घटना बीमा योजना के तहत व्यापारियों को बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई लघु व्यापारी मानधन योजना के तहत छोटे व्यापारियों को 6 हजार रुपये वार्षिक सहायता राशि प्रदान की जाती है। इतना हीं नहीं, पीएम–स्वनिधी योजना के तहत रेहड़ी–फड़ी वालों को 10 हजार रुपये से लेकर 1 लाख रुपये तक का लोन दिया जाता है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर में शिरकत करना

(दिनांक 14.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी आज बुधवार को गुरुग्राम के सेक्टर 44 स्थित अपैरल हाउस में हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान (हिपा), गुरुग्राम द्वारा आयोजित नैतिकता शिविर को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कहा कि जन सेवा के लिए सभी अधिकारी व कर्मचारी अपने व पराये के भेद से ऊपर उठकर समाज की भलाई के लिए कार्य करें। प्रदेश के साढ़े तीन लाख अधिकारियों व कर्मचारियों के मन में जनसेवा की भावना विकसित करने के लिए अब सामान्य कार्मिक प्रशिक्षण के साथ नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूक करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य है कि सरकारी सेवा में आने के उपरांत लोक सेवक के मन में यह संस्कार होना चाहिए कि उन्हें समाज की

साप्ताहिक सूचना पत्र

सेवा की जिम्मेवारी मिली है। नैतिकता बताई तो जा सकती है लेकिन इसे समझाया नहीं जा सकता। यह तो ऐसा भाव है जिसे जीवन में लाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि पिछले साढ़े आठ वर्ष के कार्यकाल में उन्हें इस बात का गर्व है कि समाज की सेवा के माध्यम से प्रदेश को आगे बढ़ाने का कार्य किया। इसी सोच पर आगे बढ़ते हुए छोटी–छोटी बातों का ध्यान कर हम अपने हरियाणा को अच्छा–दिव्य व गौरवशाली बनाने में सक्षम होंगे। इससे पहले गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने भी नैतिकता के विषय को गीता के विभिन्न श्लोकों व महाभारत से जुड़े प्रसंगों के साथ बड़े ही सहज भाव से कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को समझाया। उन्होंने नैतिकता शिविर के आयोजन को सार्थक बताते हुए हरियाणा सरकार की प्रशंसा की और गीता की उपदेश स्थली हरियाणा को इस तरह का प्रेरक कार्यक्रम नई लोकप्रियता दिलाएगा।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जल संरक्षण की पहल

(दिनांक 15.06.2023)

प्रभाव : जलवायु परिवर्तन के चलते कोरोनाकाल में जब हर कोई घर पर रहने को मजबूर था तो उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने भावी पीढ़ी को जमीन के साथ–साथ पानी भी विरासत में मिले इसके लिए मेरा पानी–मेरी विरासत एक अनूठी योजना देश के समक्ष रखी जिसकी सराहना कई मंचों में हुई है।

योजना के तहत माननीय मुख्यमंत्री जी का लक्ष्य धान बाहुल्य जिलों में धान के स्थान पर अन्य वैकल्पिक फसल की ओर जाने के लिए किसानों को प्रेरित किया और स्वयं प्रदेश के सभी 10 धान बाहुल्य जिलों के किसानों से सीधा संवाद किया।

परिणाम यह हुआ कि 1.5 लाख एकड़ भूमि पर किसानों ने धान की बजाय अन्य फसलों को अपनाया इसके लिए ऐसे किसानों को 7 हजार प्रति एकड़ की दर से वित्तीय सहायता दी जा रही

साप्ताहिक सूचना पत्र

है। वर्ष 2023–24 में इस योजना के तहत 2 लाख एकड़ क्षेत्र को धान के स्थान पर अन्य फसलों के अधीन ले जाने का लक्ष्य लिया।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने हाल ही में राज्य की द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023–25) का शुभारंभ किया। राज्य में कुल पानी की उपलब्धता 20,93,598 करोड़ लीटर है, जबकि पानी की कुल मांग 34,96,276 करोड़ लीटर है, जिससे पानी का अंतर 14 लाख करोड़ लीटर है।

इस कार्य योजना से अगले दो वर्षों के इस अंतराल को पूरा करना है। जल संरक्षण की दिशा में गत दिनों पंचकूला में दो दिवसीय जल सम्मेलन का आयोजित किया गया था, जिसमें प्रशासनिक सचिवों और जल संरक्षण पर कार्य कर रहे देश–विदेश के विशेषज्ञों ने भाग लिया था।

सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य गिरते भूजल स्तर के मद्देनजर एक एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन रणनीति और दृष्टिकोण पर चर्चा करना था। उन्हीं के इनपुट के आधार पर द्विवार्षिक एकीकृत जल संसाधन कार्य योजना (2023–25) तैयार की गई। योजना के क्रियान्वयन के लिए तीन कमेटियां गठित की गई हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई वर्षों से लंबित जल संरक्षण की किशाऊ, लखवार व रेणुका बांधों की परियोजनाओं को सिरे चढ़ाने की पहल की है इसके लिए उन्होंने केंद्र सरकार से किये गए आग्रह पर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, दिल्ली व राजस्थान के मुख्यमंत्री एक मंच पर आये और आपसी समझौतों पर हस्ताक्षर किये।

किशाऊ को तो बहुउद्देशीय (राष्ट्रीय) परियोजना घोषित किया गया।

वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने सिंचाई व जल संसाधन क्षेत्र को 6598 करोड़ रुपये का बजट में प्रावधान किया है ।

साप्ताहिक सूचना पत्र

स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद

(दिनांक 17.06.2023)

प्रभाव : माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों के लाभार्थियों से सीधा संवाद करते हुए कई बड़ी घोषणाएं की। भविष्य में राज्य में जितने भी राशन डिपो अलॉट होंगे, उनमें 33 प्रतिशत डिपो महिलाओं को देने का निर्णय सरकार ने लिया है। यदि कोई स्वयं सहायता समूह राशन डिपो के लिए आवेदन करता है तो उन्हें प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अलावा, पंचायत की जमीन या तालाब का मछली पालन के ठेके के लिए भी सेल्फ हेल्प ग्रुप आवेदन करता है तो उन्हें नीलामी की राशि में 10 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। बस स्टैंड पर भी जो दुकानें लॉटरी या किसी अन्य तरीके से आवंटित की जाएंगी तो 25 प्रतिशत सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। यदि यह दुकानें नीलामी के माध्यम से आवंटित की जाएंगी तो एसएचजी को

नीलामी की राशि में 10 प्रतिशत की छूट मिलेगी। यदि स्वयं सहायता समूह के किसी सदस्य के परिवार की आय 1.80 लाख रुपये से अधिक बढ़ती है तो 1 वर्ष के लिए उनका राशन कार्ड और आयुष्मान कार्ड नहीं काटा जाएगा।

लाभार्थियों ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा एसएचजी को रिवाल्विंग फंड, सामुदायिक निवेश फंड और क्रेडिट लिंकेज स्कीम के तहत प्रदान की जा रही वित्तीय सहायता से उन्हें व्यापार

चलाने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आती है, इसके लिए भी सरकार का बहुत धन्यवाद। एसएचजी की महिलाओं ने राज्य सरकार द्वारा विशेष रूप से महिलाओं को समाज में आगे बढ़ाने के लिए दिए जा रहे अधिकारों के लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त किया।

हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के कार्यालय में एक कॉल सेंटर स्थापित किया जाएगा ताकि सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़े लाभार्थी विभिन्न प्रकार की जानकारी प्राप्त कर सकें। प्रदेश में वर्ष 2014 में स्वयं सहायता समूहों की संख्या 812 थी। वर्ष 2014–15 में सत्ता संभालने के बाद से ही हमारी सरकार ने स्वयं सहायता समूह की ओर ध्यान दिया और पहले ही साल में 2100 नए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बने और आज साढ़े 8 साल के बाद प्रदेश में कुल 57,376 स्वयं सहायता समूह हैं। इन्हें 54 करोड़ 57 लाख रुपये रिवोलविंग फण्ड, लगभग 285 करोड़ रुपये सामुदायिक निवेश फण्ड और लगभग 880 करोड़ रुपये बैंक क्रेडिट लिकेज प्रदान किया गया है। इतना ही नहीं, सरकार ने रिवोलविंग फंड की राशि को 10,000 रुपये से बढ़ाकर 20,000 रुपये कर दी है।

प्रदेश में लगभग 6 लाख महिलाओं ने स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से सिद्ध कर दिया है कि वे समाज की सच्ची ताकत हैं। हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों व समाज में योगदान देने के लिये विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। उन्होंने संवाद के दौरान ही अधिकारियों को आदेश दिए कि एक पोर्टल विकसित किया जाए, जिस पर सेल्फ हेल्प ग्रुप द्वारा बनाए गए उत्पादों की जानकारी डाली जाए। इन उत्पादों की गुणवत्ता को सर्टिफाई कर एक ब्रांड की पहचान दी जाए ताकि लोग इस पोर्टल के माध्यम से सेल्फ हेल्प ग्रुप के उत्पाद खरीद सकें। टेक्नोलॉजी के इस युग में अपने उत्पादों के निर्माण में एसएचजी नवीनता लाएं और

प्रतियोगिता में बने रहने के लिए उत्पादों की गुणवत्ता की ओर भी विशेष ध्यान दें।

पिछले साल आयोजित स्वापन आजीविका मार्ट में एसएचजी के कौशल और दक्षता को देखने का अवसर मिला था। उसमें अनेक स्वयं सहायता समूहों की महिला कारीगरों एवं शिल्पकारों ने भाग लिया था। उस मेले में हथकरघा और हस्तशिल्प के उत्पाद प्रदर्शित किये गये थे। वर्ष 2023 को अंतरराष्ट्रीय मोटे अनाज वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है। एसएचजी भी मोटे अनाजों के उत्पाद बनाना शुरू करें। आजादी के अमृत महोत्सव में हर घर तिरंगा अभियान के लिए महिला स्वयं सहायता समूहों द्वारा बनाये गये तिरंगे ने भारत का गौरव बढ़ाया है। कोरोना काल में मास्क बनाकर इस बीमारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भी योगदान दिया। सरकार ने प्रदेशभर में 144 कैंटीन भी स्वयं सहायता समूहों को संचालन के लिए दी हुई हैं। एसएचजी के लिए विभिन्न प्रकार के

प्रशिक्षण देने की व्यवस्था की गई है। कम्प्यूटर का प्रशिक्षण प्राप्त कर तथा भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय संस्थान से उत्तीर्ण होकर 773 महिलाएं बैंक सुविधा प्रदाता के तौर पर काम कर रही हैं। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए राज्य सरकार ने पंचायती राज संस्थाओं में 50 प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिया गया है।

उन्होंने कहा कि स्वयं सहायता समूह के

साप्ताहिक सूचना पत्र

सदस्यों को आजीविका के वैकल्पिक स्रोत उपलब्ध करवाने के लिए आजीविका ग्रामीण एक्सप्रेस योजना के तहत 149 लाभार्थियों को वाहन हेतु 5 करोड़ 41 लाख रुपये की ब्याज रहित राशि उपलब्ध करवाई गई है। सरकार ने ग्रामीण गरीब परिवारों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना और विभिन्न कार्यक्रमों के जरिये उनकी गरीबी को दूर करने के लिए हरियाणा राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन शुरू किया है। इस मिशन से जुड़ी हुई महिलाओं को सराहनीय कार्यों व समाज में योगदान देने के लिये विभिन्न संस्थाओं व संगठनों द्वारा सम्मानित किया गया है। महिलाएं जिस काम को ठान लेती हैं, उस काम में सफलता अवश्य मिलती है। इसके सफल उदाहरण बेटी बचाओ – बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान हैं।

साप्ताहिक सूचना पत्र

जिला सिरसा में भारत गौरव रैली का आयोजन

(दिनांक 18.06.2023)

प्रभाव : केंद्रीय गृह मंत्री माननीय श्री अमित शाह जी ने जिला सिरसा में आयोजित गौरवशाली भारत रैली में उपस्थित जनसमूह को सम्बोधित किया।

उन्होंने प्रधानमत्री जी के पीछले 9 साल की उपलब्धियों और देश में हुए विकास कार्यों का जिक्र भी किया। साथ ही उन्होंने माननीय मुख्यमंत्री जी की भी सराहना करते हुए कहा उन्होंने हरियाणा में भ्रष्टाचार को जड़ से समाप्त करने का काम किया है। उन्होंने पिछली सरकार के कार्यकाल पर तंज कसते हुए कहा कि राज्य में कांग्रेस की सरकार थ्री–डी की सरकार थी। थ्री–डी यानी दरबारी, दामाद और डीलर। मनोहर लाल ने इन तीनों डी को समाप्त कर दिया है।

केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि इन 9 साल में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पारदर्शी तरीके से शासन उपलब्ध करवाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार के कार्यकाल के दौरान

साप्ताहिक सूचना पत्र

केंद्र और राज्य में कांग्रेस की सरकार थी। उस समय वर्ष 2004 से 2014 तक हरियाणा को डीवैल्यूशन और ग्रांट इन ऐड के कुल मिलाकर 40,000 करोड़ रुपये दिये थे। जबकि माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस राशि को बढ़ाकर 1 लाख 30 हजार करोड़ रुपये हरियाणा को दिए हैं।

उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश का गौरव दुनिया में बढ़ा है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को माननीय मुख्यमंत्री जी ने जमीनी स्तर तक पहुंचाया और पूरे हरियाणा का विकास करने का काम किया। हरियाणा का धाकड़ जवान, धाकड़ किसान और धाकड़ खिलाड़ी ये तीनों देश की शान हैं। उन्होंने कहा कि जब भी हरियाणा आता हूं, इस बात को याद करता हूँ कि जब भी देश पर संकट आया तो पंजाब–हरियाणा की भूमि ने चट्टान बनकर देश के दुश्मनों के सीने छलनी कर दिए। मैं हरियाणा की वीरांगना

माताओं को भी नमन करता हूँ, जिन्होंने देश को अनेक बलिदानी बेटे दिए, जिन्होंने हंसते–हंसते भारत माता की सुरक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए।

हरियाणा खिलाड़ियों की भूमि है। देश को जब भी मेडल मिलता है तो हर तीसरा खिलाड़ी हरियाणा से होता है। मनोहर सरकार ने पिछले साढ़े 8 सालों में खिलाड़ियों के लिए अनेक योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों से माननीय प्रधानमंत्री जी देश की सेवा कर रहे हैं। हरियाणावासियों ने

साप्ताहिक सूचना पत्र

दो बार लोकसभा की सभी की सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में डालकर श्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, इसके लिए वे हरियाणा की जनता का धन्यवाद करते हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 9 सालों में हरियाणा देश का सबसे पहला कैरोसीन मुक्त राज्य बना। देश का सबसे पहला पढ़ी–लिखी पंचायतों वाला राज्य बना। हरियाणा की विकास दर वर्ष 2015 से 2022 तक 6 प्रतिशत से ज्यादा रही है। मोदी और मनोहर की डबल इंजन की सरकार ने हरियाणा के विकास में कोई कमी नहीं छोड़ी। उन्होंने कहा कि वर्ष 2019 से अब तक राज्य को 5.22 बिलियन डॉलर का विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने कभी 6 हजार रुपये किसानों के खातों में सीधे नहीं भेजे और न ही फसल विविधिकरण के लिए किसानों को जागरूक करने का काम किया। जबकि मनोहर सरकार किसानों के लिए भावांतर भरपाई योजना लेकर आई और किसानों को जागरूक कर फसल विविधिकरण को बढ़ावा दिया। 20 लाख किसानों को हर साल 6000 रुपये मिल रहे हैं। जल जीवन मिशन के तहत 30 लाख घरों तक नल से जल पहुंचा है। 82 लाख लोगों को आयुष्मान भारत योजना का लाभ मिल रहा है।

साप्ताहिक सूचना पत्र

प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 75,000 से ज्यादा घर बने हैं।

केंद्रीय गृह मंत्री जी ने कहा कि देश के माननीय प्रधानमंत्री जी ने गृह मंत्रालय के सामने भारत को नशा मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा। यह अभियान हरियाणा में भी शुरू हुआ है। उन्होंने कहा कि 5 मई, 2019 का दिन देश के लोगों के लिए एक ऐतिहासिक था, जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने जम्मू–कश्मीर से धारा 35–ए हटाने का कार्य किया था। उन्होंने कहा कि सिरसा में बहुत कार्य किए गए हैं। 1513 करोड़ रुपये का किसानों को बीमा क्लेम दिया गया है।

माननीय राष्ट्रपति जी ने 22 एकड़ भूमि पर 1000 करोड़ रुपये की लागत से मेडिकल कॉलेज की आधारशिला रखी। सिरसा फतेहाबाद मार्ग का निर्माण चल रहा है। कई नए पुल बन रहे हैं।

सिरसा के तेजाखेड़ा आसाखेड़ा और चौटाला की जमीन पर मेगा फूड पार्क बन रहे हैं। सिरसा में एक नए जल उपचार संयंत्र का निर्माण हुआ है और सौर ऊर्जा केंद्र भी सिरसा में बन रहे हैं।

माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में विश्व में भारतवर्ष का स्थान ऊंचा हुआ है। आज विश्व के अंदर भारत का नाम

बढ़ा है और जैसे भारत पहले दुनिया का विश्वगुरु कहलाता था, वैसे ही निकट भविष्य में भी दुनिया फिर से भारत को विश्वगुरु कहेगी। पिछले 9 वर्षों में हरियाणा सरकार ने केंद्र सरकार की सभी योजनाओं को पूरी तरह लागू किया है। प्रदेश में पहले भ्रष्टाचार का बोलबाला था और भय का वातावरण था, इससे वर्तमान राज्य सरकार ने जनता को बहुत राहत दिलाई है। उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि न खाऊंगा, न खाने दूंगा। हरियाणा सरकार ने उनके इस कथन पर चलते हुए प्रदेश में भ्रष्टाचार को समाप्त किया। गरीबों के उत्थान के लिए हमने अंत्योदय की भावना से बहुत योजना बनाई है। राज्य सरकार ने परिवार पहचान पत्र लागू करके हर गरीब को सरकार की योजनाओं का लाभ उनके घर द्वार पर दिया है।